भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2338
गुरुवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

महाराष्ट्र में विमानन ढांचे का उन्नयन

2338. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में छोटे विमानपत्तनों और उनकी कार्यात्मक स्थिति का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विमानपत्तनों के विस्तार और विमानन अवसंरचना के उन्नयन के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार के पास कोविड-19 महामारी के बाद विमानपत्तनों को सहायता देने के लिए की गई-कार्रवाई पर कोई रिपोर्ट/मूल्यांकन उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) महाराष्ट्र में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके पूरा होने की स्थिति क्या है तथा उक्त परियोजनाओं के लिए, विशेष रूप से परभणी संसदीय क्षेत्र में, कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है; और
(च) क्या सरकार का वाशिम यवतमाल संसदीय क्षेत्र सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में विमानन अवसंरचना को विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): महाराष्ट्र में औरंगाबाद, गोंदिया, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, शिरडी, सिंधुदुर्ग, अकोला, जलगांव, जुहू, नांदेड़ और सोलापुर में 14 हवाईअड्डे प्रचालनरत हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य में छह (6) हवाईअड्डे नामतः कोल्हापुर, जलगांव, नांदेड़, नासिक, गोंदिया और सिंधुदुर्ग पहले ही प्रचालनरत हो चुके हैं।
(ख) से (च): हवाईअड्डों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इसे संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा यात्री मांग के पूर्वानुमान, विमान परिचालन की संरक्षा के लिए परिचालन आवश्यकताओं और एयरलाइनों की मांग के आधार पर किया जाता है। विकास कार्य भूमि की उपलब्धता और व्यवहार्यता के साथ-साथ इच्छित विमान परिचालन के संदर्भ में अन्य सुविधाओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय

विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने महाराष्ट्र के अकोला, औरंगाबाद, गोंदिया, जुहू, कोल्हापुर, पुणे और सोलापुर हवाईअड्डों पर हवाईअड्डों के विस्तार और विमानन अवसंरचना के उन्नयन के लिए विभिन्न परियोजनाएं आरंभ की हैं, जिनमें रनवे का विस्तार/री-कार्पेटिंग, टर्मिनल भवनों का निर्माण/पुनर्संरचना, एप्रन और टैक्सीवे का विस्तार आदि शामिल हैं।

जहां तक चल रही परियोजनाओं का प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 61.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शिरडी हवाईअड्डे पर रनवे और टैक्सीवे की री-कार्पेटिंग का कार्य आरंभ किया है, जिसमें से अब तक 6.78 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। नागपुर हवाईअड्डे पर, रनवे 14/32 की री-कार्पेटिंग का कार्य 58.00 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है, जिसमें से 19.13 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इसी प्रकार, पुणे हवाईअड्डे पर पुराने टर्मिनल भवन का पुनर्निर्माण और संबद्ध कार्य 46.56 करोड़ रुपये की लागत से आरंभ किया गया है, जिसमें से अब तक 25.86 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। ये परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं।

यवतमाल हवाईपट्टी, उड़ान योजना के दस्तावेज़ में असेवित हवाईपट्टियों की सूची में शामिल है। तथापि, आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए यवतमाल को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग किसी भी एयरलाइन को अवार्ड नहीं किया गया है।

महामारी के पश्चात हवाईअड्डों को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने कतिपय शर्तों के अध्यधीन, निष्पादन गारंटी में कमी और अतिरिक्त निष्पादन गारंटी वापस लिए जाने जैसे अस्थायी वित्तीय लचीलेपन की शुरुआत की हैं। इसके अतिरिक्त, परिचालन संबंधी लचीलापन भी प्रदान किया गया था, जिसमें आरसीएस सीटों को गैर-आरसीएस सीटों में परिवर्तित करना, प्रति सप्ताह 3 से 7/14 उड़ानें परिचालित करने की अनुमति, निष्पादन मानदंडों का स्थगन और लॉकडाउन अवधि के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार शामिल है।

******